Textile processing activity has been brought within the purview of Textiles (Development and Regulation) Order, 1993.

Anti-Dumping Laws Imposed by European Commission on Indian Textiles

2699. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the Minister of EXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that exports worth more than Rs. 880.00 crore which include exports of unbleached cotton fabric worth Rs. 640.00 crore, bed linen worth Rs. 240.00 crore besides shop towels and gauze cloth are at state due to anti-dumping laws imported by European Commission in respect of exports to European Union countries;

(b) if so, the action taken by Government to protect the interest of Indian exporters;

(c) whether European Commission had fixed any criteria for invoking the anti dumping laws; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R. L. JALAPPA): (a) It is true that exports worth Rs. 600 crores of unbleached cotton fabrics may attract anti-dumping duties under the antidumping proceedings initiated by the European Commission in respect of exports of this item to the member states of the European Union. The European Commission has also recently initiated anti-dumping proceedings relating to import of cotton type bed-linen into the EU Members from several countries, including India.

(b) The Government through the Embassy of India, Brussels, have been actively pursuing the matter with the concerned authorities in the European Commission., Besides, the Cotton Textiles Export Promotion Council, Mumbai (TEXPROCIL) has been acting as the nodal agency for co-ordinating the efforts of individual exporters in representing their cases.

(c) and (d) The European Commission has initiated the proceedings on the basis of Council Regulation No. 384/96 dated 22.12.1995 which sets out the principles and methods to be adopted for investigating and imposing anti-dumping duties.

Cotton stocks piling up due to Bumper Crop.

2700. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that stocks of cotton are piling up due to bumper crop during the current year and slow release of export quotas and less demand by the textile mills as compared to last year;

(b) if so, the details thereof and the steps taken/proposed to be taken to deal with the problem;

(c) the target set for export of cotton during the current year and the quota released to the State Governments; and

(d) the details of the proposal received from Government of Maharashtra and action taken/proposed to be taken thereon in looms of the New Policy formulated?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R. L. JALAPPA): (a) The Cotton Advisory Board in its meeting on 24/2/ 97 has estimated the current crop size to be 160 lakh bales. Daily arrivals of cotton in the market are heavy. Government released substantial export quotas early in the season and even subsequently, in order that there may not be piling of stocks.

(b) Does not arise.

(c) No target is set by the Government for export of cotton. However, export quotas for cotton are announced by the Government after taking into consideration all relevant factors, including estimates of production, availability, consumption, likely surplus, price trends, etc. No export quota is released to the State Governments.

However, export quotas totalling 12.20 lakh bales of cotton have been released to various State Cooperative Marketing Federations and other agencies, including the private ginners/trade during the current cotton season (1996-97), as on date. Of this quantity, quota of 4.10 lakh bales have been allotted to various State Federations/Corporations, besides another 4.65 lakh bales allotted to CCI and NAFED.

(d) During the 1996-97 season, till 26/12/96, the Maharashtra State Cooperation Cotton Growers Marketing Federation Ltd. have been allotted an export quota of 1 lakh bales. The Federation has requested for release of a further export quota of two lakh bales of cotton. Allocations are considered only after taking into account all relevant factors.

सरकार द्वारा आयोजित हस्तशिल्प मेले

2701. **श्री रामजीलाल**:
श्री अजीत जोगी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितने हस्तशिल्प मेले आयोजित किए जा रहे है;

(ख) इन मेलों में भाग लेने के लिए शिल्पकारों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाये जा रहे है;

(ग) इन मेलों में अर्जित कुल आय को आयोजकों और शिल्पकारों में किस प्रकार वितारित किया जाता है; और

(घ) ऐसे मेलों के आयोजनों से इन शिल्पकारों और आयोजकों ने कितना-कितना लाभ अर्जित किया?

वस्त्र मंत्री (श्री आर0एल0 जालप्पा): (क) सरकार प्रतिवर्ष लगभग 60 हस्तशिल्प मेले आयोजित करती है।

(ख) इन मेलों में भाग लेने वाले शिल्पियों का चयन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तैयार की गई कारीगरों की सूची के आधार पर किया जाता है। तथापि, राष्ट्रीय/ राज्य पुरस्कार विजेताओं, श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वालो, लुप्तप्राय: शिल्पों में कार्यरत शिल्पियों, वृद्व तथा महिला शिल्पियों और समाज के कमजोर वर्ग से सम्बन्धियों को वरीयता दी जाती है। सामान्यत: एक बार चयनित शिल्पकर को अगले तीन वर्षो तक दूसरा अवसर नहीं दिया जाता।

(ग) और (घ) इन मेलों का मुख्य उद्देश्य शिल्पियों को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने के लिए प्लेटफार्म प्रदान करना है और उनके द्वारा उपर्जित आय का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। सरकार को इन मेलों में कोई आय नहीं होती।

वस्त्र उद्योग से वसूल की गई बिजली की दरों में अन्तर

2702. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में त्रिपुरा और गुजरात में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में वसूल की जाने वाली बिजली दरों में अत्याधिक अंतर है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है और क्या त्रिपुरा और गुजरात में बुनकरों को महंगी दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित्त विद्युत दर से अलग दर राज्य में बुनकरों से वसूल की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करने का विचार रखती है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर0एल0 जालप्पा): (क) से (घ) विद्युत प्रभार लगाने से संबंधित मामला राज्य सरकार/राज्य विद्युत बोर्ड का विषय है। वस्त्र मंत्रालय ने विद्युतकरघा बुनकरों पर लगाये जाने वाले कोई विशेष विद्युत प्रभारों को निर्धरित नहीं किया है।

गुजरात कच्चा कपास खरीद एकाधिकार योजना

2703. **श्री गोपाल सिंह जी0 सोलंकी**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात कच्चा कपास खरीद एकधिकार योजना को दीर्घावधि विस्तार प्रदान करने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस पर शीघ्र निर्णय करने के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो विलंब के कारण क्या है?